प्रैस विज्ञप्ति

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निम्नलिखित बयान जारी किया है:-

1. 'जय जवान-जय किसान' का लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा हमारे देश का ध्येय व धर्म रहा है। दुर्भाग्य से, मोदी सरकार में आज 'जवान और किसान' दोनों का राजनीतिक शोषण किया जा रहा है। सच यह है कि जवानों की शहादत का सत्ता के लिए अपमान और न ही रखते किसानों के परिश्रम का मान।

2. आज देश के 'जवान की शहादत' पर भाजपा राजनीतिक रोटियां सेक रही है।
   * शहीदों की कुर्बानी का इस्तेमाल यूपी और पंजाब के चुनाव में वोट बटोरने के लिए किया जा रहा है।
   * देश की सेना बलिदान दे और मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान राम का अवतार नरेन्द्र मोदी जी को बताया जा रहा है।
   * जान की कुर्बानी सैनिक दे और महिमामंडन नरेन्द्र मोदी जी का हो।
   * पाकिस्तान और उग्रवाद के खिलाफ पराक्रम सेना का और 100 इंच का सीना नरेन्द्र मोदी जी का।
   * भारत के तिरंगे में लिपट शहादत जवानों की और गोवा से आगरा-लखनऊ तक सम्मान समरोह रक्षा मंत्री, श्री मनोहर पारिकर का।
   * भाजपा की राजनैतिक ब्यानबाजी, श्रेय लूटने की होड़, होर्डिंग व पोस्टरबाजी से साफ है कि सैन्य पराक्रम और 'सर्जिकल स्ट्राइक' की वीरगाथा को भी भाजपा वोट हथियाने के लिए इस्तेमाल करने की शर्मनाक कोशिश कर रही है।

3. भाजपा और उनका शीर्ष नेतृत्व शर्मनाक तरोके से 68 साल की सेना की बहादुरी, वीरता, शहादत व पराक्रम का अपमान करने में लगी है।

   I. एक अक्तूबर, 2016 को रक्षा मंत्री, श्री मनोहर पारिकर कहते हैं कि मोदी सरकार ने पहली बार सेना को अपनी ताकत का एहसास करवाया।

   He specifically said, "Indian Troops were like Hanuman who did not quite know their prowess before this surgical strike".

   II. 01 अक्तूबर, 2016 को ही मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान अंहकारी तरीके से कहते हैं कि अब मोदी जी का सीना 100 इंच का हो गया है।

   III. 7 अक्तूबर, 2016 को भाजपा अध्यक्ष, श्री अमित शाह दिल्ली में एक पत्रकार गोष्ठी में घमंडपूर्वक उद्घोष करते हैं कि 68 वर्ष में पहली बार सेना ने लाईन ऑफ कंट्रोल पार की है।

   अमित शाह जी ने तो खुलेआम ऐलान कर डाला कि वो सर्जिकल स्ट्राइक को पूरे देश में लेकर जायेंगे यानि राजनीतिक रोटियां सेक कर उसे भी भुनायेंगे।

   IV. और कल 9 अक्तूबर, 2016 को स्वयं प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी भी सेना की शहादत का श्रेय लेने की इसी पंक्ति में शामिल हो गए और परोक्ष रूप से टिप्पणी भी की।

V. मोदी सरकार ने भारतीय सेना की बहादुरी, शौर्य, वीरता और पराक्रम को भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगने का अपराध किया है। कल 9 अक्तबूर, 2016 को सेना की असीम बहादुरी वाली एक और सर्जिकल स्ट्राइक 'आपरेशन जिंजर' का सार्वजनिक खुलासा हुआ। यह स्पष्ट तौर से सामने आया कि 30 अगस्त/01 सितंबर, 2011 को भारतीय सेना के पैरा कमांडोज़ ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर 'सर्जिकल स्ट्राइक' की और दुश्मन के 13 सैनिकों का मार गिराया, इसकी पुष्टि स्वयं मेजर जनरल एस.के.चक्रवर्ती द्वारा की गई है, जो इस ऑपरेशन के मुखिया थे।

* पूर्व सेना अध्यक्ष, जनरल बिक्रम सिंह के कार्यकाल में हुई जुलाई 2013 व 14 जनवरी, 2014 की सर्जिकल स्ट्राइक्स की पुष्टि पहले से ही कर चुके हैं। अनेकों पूर्व सेना अधिकारियों समेत लै. जनरल पी.एन.हून व लै. जनरल एच.एस. पनाग भी सार्वजनिक पटल पर हमारी सेना की सर्जिकल स्ट्राइकस की बहादुरी को कहानी बता चुके हैं।

* ऐसे में मोदी सरकार का अहंकार व झूठी राजनीतिक शान भरतीय सेना की शहादत का अपमान कर रही है। झूठ पर झूठ बोलकर भाजपा अध्यक्ष, श्री अमित शाह, रक्षा मंत्री श्री मनोहर पारिकर, कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रशाद व भाजपाई नेता 68 साल की सेना की कुर्बानी के इतिहास को गौण बनाने में लगे हैं।

  कम से कम मोदी सरकार शहीद सुबोध की पत्नी श्रीमती सीमा की या फिर श्री हेमराज की पत्नी श्रीमती धर्मवती की शहादत का राजनैतिकरण न करने की अपील से ही सीख लेलें।

* एक तरफ सर्जिकल स्ट्राक्स का श्रेय लेने की होड़ है तो दूसरी तरफ सेना के साथ भेदभाव वाला व्यवहार। छद्म राष्ट्रवाद और देश की सेना का एकमात्र शुभचिंतक होने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने आज तक क्यों 'वन रैंक-वन पैंशन' लागू नहीं किया? क्या यह सच नहीं कि देश के पूर्व सैनिक 'वन रैंक-अनेक पैंशन' के चलते अपने-आपको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में जो कमियां तीनों सेना प्रमुखों द्वारा सरकार को बताई गयी थी, उन्हें सिरे से क्यों खारिज कर दिया गया? और हद तो तब हो गई जब 30 सितंबर 2016 को आदेश जारी कर मोदी सरकार द्वारा युद्ध या सजिकल स्ट्राइक में घायल होने वाले फौजी जवानों व अफसरों का 'डिसएबिलीटी पैंशन' आधे से कम कर दी गई। अब सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले कमांडोज़ की 100 प्रतिशत 'मासिक डिसएबिलीटी पैंशन' रूपए 45,200 से घटाकर रूपया 27,200 कर दी गई है। सर्जिकल स्ट्राइक को लीड करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों की पैंशन भी इसी प्रकार 70 हजार रूपए कम कर दी गई है। जूनियर कमीशनड अधिकारियों की 'डिसएबिलीटी पैंशन' भी 40 हजार रूपए माह तक कम कर दी गई है। क्या उग्रवादियां पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का यही तोहफा मोदी सरकार ने भारत की सेना को दिया है।

4. हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी व भाजपा अध्यक्ष, श्री अमित शाह भारत की सेना से बगैर शर्त माफी मांगे और सार्वजनिक तौर पर यह वायदा करे कि सेना की शहादत, वीरता, कुर्बानी व बलिदान का राजनीतिकरण नहीं होगा। सातवें वेतन आयोग से जुड़े मुद्दों का समाधान करेंगे। 'वन रैंक-वन पैंशन' लागू करेंगे व 30 सितंबर, 2016 का सेना की 'डिसएबिलीटी पैंशन' आदेश को वापस लेंगे।